

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा



सीटाराम अधिकारी- अविचल चतुर्वेदी
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 32/2019

सुखदेव पुत्र भौरया जाति मीना निवासी ग्राम रुढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।
.. अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 29.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सुखदेव मु०सं० 166/2018 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री सीताराम मीना , अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 02.07.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 29.10.2018 को ग्राम रुढमल का बास तहसील दौसा के आ०ख० 61 रकबा 0.10 है० किस्म चरागाह पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो० को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांत ने किसी भी चरागाह मूनि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांत को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच किये बिना निर्णय पारित किया है। कानूनन अपीलांत को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए अस्मात्पूर्व आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांत लोकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें ।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कौफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फसल जब्ती एवं निलामी की रिपोर्ट संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलांत द्वारा वरवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 61 रकबा 0.10 है० किस्म चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांत के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 02 जुलाई, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

